आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 29.03.2025
समय 0720

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने खरीफ–2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भागीरथ मोबाइल एप का शुभारंभ किया। संकटग्रस्त जल स्रोतों के संरक्षण में मदद मिलेगी।
- प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों में 84 बॉण्डधारी चिकित्सकों की तैनाती, दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी।
- निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु ने प्रदेश में चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों को लेकर देहरादून में समीक्षा बैठक की।

मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ–2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुये सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक सस्ती और सब्सिडी युक्त कीमतों पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सिंगल सुपर फॉस्फेट पर माल ढुलाई सब्सिडी को भी खरीफ 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

भागीरथ एप

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम– ''धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा'' पर आधारित भागीरथ मोबाइल एप का शुभारंभ किया। इस एप के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र के संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे। एप के माध्यम से चिन्हित स्रोतों का प्रदेश सरकार, पुनर्जीवीकरण की दिशा में काम करेगी। देहरादून में जल संरक्षण अभियान के तहत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जल स्त्रोतों, नौलों, धारों और वर्षा आधारित नदियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी– सारा का गठन किया है। सारा ने गत वर्ष विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित कर प्रदेश के लगभग 6 हजार 500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए उपचार कार्य किया। साथ ही लगभग 3 दशमलव 1–2 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करने में भी सफलता प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सारा द्वारा मैदानी क्षेत्रों में केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के सहयोग से भू–जल रिचार्ज के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के अपने पहले चरण में तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर नयार, सौंग, उत्तरवाहिनी शिप्रा व गौड़ी नदी के उपचार के लिए आई०आई०टी०, रूड़की तथा एन०आई०एच० रूड़की के सहयोग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के अभियान को ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक व्यापक रूप से चलाया जायेगा।

उच्च न्यायालय

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को पालिका के उन कर्मचारियों की सूची पेश करने का निर्देश दिया हैं, जिनके नाम नजूल भूमि फ्रीहोल्ड हुई है। मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष नैनीताल के मल्लीताल स्थित पौनिसराय फ्री होल्ड नजूल भूमि प्रकरण की सुनवाई हुई। इस मामले में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने न्यायालय को बताया कि आरोपी तत्कालीन नजूल क्लर्क के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

बहुउद्देशीय शिविर

प्रदेश सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूरा होने पर देहरादून में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर ने लाभार्थियों को चैक वितरित किए। शिविर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास सहित सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। शिविर में 773 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला।

नकद निकासी

रिजर्व बैंक ने पहली मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन–एटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रुपये की वृद्धि करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि मुफ्त लेनदेन से अलग, ग्राहक से प्रति लेनदेन अधिकतम 23 रुपये का शुल्क लिया जा सकता है। यह पहली मई से लागू होगा।

बॉण्डधारी चिकित्सक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 84 नए एमबीबीएस चिकित्सक मिल गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर से पास आउट इन बॉण्डधारी चिकित्सकों को प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों में तैनाती दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के चिकित्सा इकाइयों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चीकरण के लिये राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों सहित विभिन्न संवर्गों में पैरामेडिकल स्टॉफ की तैनाती से स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। इसी क्रम में बॉड व्यवस्था के तहत श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पास आउट 84 बॉण्डधारी चिकित्सकों को नौ पर्वतीय जनपदों में तैनाती दे दी गई है, जिसकी सूची स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दी गई है। सीएमओ इन चिकित्सकों को प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों के अनुसार अस्पतालों में नियुक्त करेंगे। डॉ. रावत ने कहा कि बॉण्डधारी एमबीबीएस चिकित्सकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में दी जायेगी। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती से स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को उपचार मिल सकेगा।

निर्वाचन अयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु ने देहरादून में प्रदेश में संचालित चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक की। डॉ संधु ने मतदेय स्थल तक मतदाताओं की पहुंच सुनिश्चित करने और उनकी सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी नियमों, अधिनियमों, प्राविधानों व कानून की समुचित जानकारी होने पर भी बल दिया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य में सभी स्तरों पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक हो चुकी है। इस दौरान राजनैतिक दलों से प्राप्त सुझावों से भी डॉ. संधु को अवगत कराया गया।

नगर पालिका बैठक पौड़ी

पौड़ी में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष हिमानी नेगी की अध्यक्षता में शहर की समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए माउंटेन बाइकिंग जैसे कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और अतिक्रमण जैसे जरूरी मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। पर्यटन विभाग से अपेक्षा की गई कि बस अड्डे में नगर के मुख्य स्थानों की दूरी प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्ड लगायें, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

बैठक अल्मोड़ा

अल्मोड़ा जिले को नशा मुक्त बनाने और नशे की प्रवृतियों से दूर रखने को लेकर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेस अस्पताल में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के खोलने और उसके संचालन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने केंद्र के संचालन की शर्तें और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।

एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की ख़बर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई, कर्मचारियों का डीए बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य फैसले को दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाया है। समाचार पत्र लिखता है– इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिये तेईस हजार करोड़ की स्कीम मंजूर।

वरिष्ठ आई.ए.एस अधिकारी आनंद बर्द्धन उत्तराखंड के नये मुख्य सचिव होंगे। इस ख़बर पर अमर उजाला ने लिखा है– 31 मार्च को कार्यकाल पूरा कर रही रतूड़ी की जगह लेंगे आनंद बर्द्धन।

एक अन्य ख़बर पर अमर उजाला का शीर्षक है– नौ पर्वतीय जिलों में तैनात किये गये 84 बांडधारी डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत के हवाले से समाचार पत्र लिखता है– सभी डॉक्टरों को बीस दिनों के भीतर ज्वाइन करना होगा।

केंद्र ने अतिरिक्त बिजली में 20 प्रतिशत कोटा उत्तराखंड के लिये स्वीकृत किया है। दैनिक जागरण समाचार पत्र के अनुसार राज्य को अगले पांच महीने में अतिरिक्त कोटे के रूप में शेष बिजली का बीस प्रतिशत आवंटित करने का पत्र जारी कर दिया गया है।